Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025
fb: https://www.facebook.com/PopularFrontofIndiaOfficial/ website: www.popularfrontindia.org email: popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
6 फरवरी 2018

पॉपुलर फ्रंट का बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम का ऐलान

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की केंद्रीय सचिवालय की बैठक ने 11वें 'पॉपुलर फ्रंट डे' के अवसर पर एक 7 दिवसीय जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि 17 फरवरी 2007 को एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऐलान किया गया था। जिसे याद करते हुए इस वर्ष भी 17 फरवरी को ''पॉपुलर फ्रंट डे'' मनाया जाएगा, जिसका नारा ''हम अवाम के साथ; अवाम हमारे साथ'' होगा। इस सिलसिले में पहले 6 दिनों को जनसंपर्क सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा और संगठन के संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अवाम तक पहुँचाने के लिए देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान में जनसभा, यूनिट स्तर पर झंडारोहण, वालंटियरों के द्वारा यूनिटी मार्च, सामाजिक सेवा और सोशल मीडिया जैसे विभिन्न प्रोग्राम शामिल होंगे। 11 फरवरी को सभी यूनिटें पूरे भारत में घर घर जाकर लोगों से मुलाक़ात करेंगी और संगठन का परिचय कराएंगी।

बजट 2018: दावों का हक़ीक़त से कोई वास्ता नहीं

बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी सरकार जनता से किये गए अनेक वादों में से किसी एक को भी पूरा नहीं कर पाई है। इस सरकार ने नोटबंदी जैसे अजीब व गरीब फैसलों के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। बजट 2018 के बारे में जितने भी दावे किये गए हैं उनका हक़ीक़त से कोई वास्ता नहीं है। इससे सिर्फ अमीरों को फायदा मिलेगा और गरीब भारतीय नागरिकों की बड़ी आबादी की परेशानियाँ और बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य, खेती–बाड़ी और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का ऐलान करके बजट को गरीबों और किसानों का बजट बताया जा रहा है। लेकिन इन योजनाओं के लिए जो नाकाफी बजट तय किया गया है, उससे पता चलता है ये सभी ऐलान केवल जनता को लुभाने के लिए किये गए हैं और इनका हक़ीक़त से कोई वास्ता नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि क़र्ज़ माफी के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया, जबकि किसानों को अब तक अपना क़र्ज़ चुकाना पड़ रहा है। जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बजाए जिस पर गरीबों का जीवन निर्भर करता है, बजट में स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं जारी की गई हैं। इससे सिर्फ बीमा कंपनियों और प्राइवेट अस्पतालों की ही जेबें भरेंगी। इसी तरह देश के कुछ बेहद अमीर लोगों के लिए 'प्रत्यक्ष कर' के नए तरीकों को सुनिश्चित करने के

बजाए, बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को और कम कर दिया गया है। इसके अलावा उसमें अधिक नए 'अप्रत्यक्ष करों' का ऐलान किया गया है, जिसका सीधा प्रभाव आम लोगों पर होगा। शिक्षा के बजट में कटौती भी एक बड़ी ख़तरनाक बात है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, शिक्षा के बजट में बहुत तेज़ी से कमी की गई है। यह इस बात का खुला इशारा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के अधिक से अधिक निजीकरण के लिए इससे खुद को अलग कर रही है।

कासगंजः संघ परिवार फिर से दंगों की राजनीति करते हुए

बैठक में यह भी कहा गया कि कासगंज हिंसा और उसके बाद निर्दोष मुस्लिम नौजवानों को पुलिस द्वारा परेशान किये जाने से पता चलता है कि संघ परिवार 2019 लोकसभा चुनावों के मद्दे नज़र राज्य में एक बार फिर से दंगों की राजनीति कर रहा है। कई सूत्रों से मिलने वाली रिपोर्टों से ज़ाहिर होता है कि संघ परिवार के गुंडों ने ही गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगे मुस्लिम नौजवानों पर हमला किया था। हैरत की बात यह है कि सीसीटीवी फूटेज में पुलिस हिंसा को रोकने के बजाए मुसलमानों पर हमला करने में अपराधियों का साथ देती नज़र आ रही है। एस. आर. दारापुरी के नेतृत्व वाली टीम के द्वारा प्रकाशित फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अनुसार, दो मस्जिदों और मुसलमानों की 30 दुकानों को जला दिया गया, जबकि किसी भी हिंदू घर या मंदिर पर आंच तक नहीं आई। पुलिस चुन चुन कर मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही है। जो मुसलमान इलाक़ा छोड़कर चले गए हैं, वे पुलिस के डर से वापस आने में हिचकिचा रहे हैं। बीजेपी ने हमेशा ही या साबित किया है कि वह देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के बिना चुनाव जीतने के क़ाबिल नहीं है। आज केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर अपनी सरकार होने के बावजूद, संघ परिवार के पास जनता के जीवन में बेहतरी लाने के लिए कुछ भी नहीं है। जहाँ बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हों, वहाँ गायों के लिए एम्बुलेंस की सेवा देने में लगी सरकार के साथ जनता बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रही है। बीजेपी सरकार का सबसे आसान हथियार यह है कि जनता के गुस्से को अल्पसंख्यकों की ओर मोड़ दिया जाए। बैठक ने कहा कि गुजरात विधानसभा और विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों के परिणाम से यह साबित होता है कि जनता साम्प्रदायिक पागलपन और हिंसा के बजाए भाईचारा और विकास चाहती है।

बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन ई. अबूबकर ने की। महासचिव एम. मुहम्मद अली जिन्ना, वाइस चेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य अनीस अहमद, ई.एम. अब्दुर्रहमान, अब्दुलवाहिद सेठ, ए.एस. इस्माईल, पी. कोया और के.एम. शरीफ वग़ैरह ने बैठक में हिस्सा लिया।

डॉ० मुहम्मद शमून
डाएरेक्टर, जनसंपर्क
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
मुख्यालय, नई दिल्ली